

## हरिसत में होने वाली मौतों पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता

### प्रलिस के लिये:

हरिसत में यातना, मानवाधिकार, हरिसत में मौत, अनुच्छेद 21, IPC, CrPC।

### मेन्स के लिये:

हरिसत में यातना और हरिसत में मौत, पुलिस व्यवस्था में सुधार, प्रौद्योगिकी और पूछताछ, हरिसत में मौत से बचने के उपाय

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हरिसत में मौत के मामलों में आरोपित पुलिस अधिकारियों की ज़मानत याचिकाओं पर विचार करते समय "अधिक कठोर दृष्टिकोण" अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

## हरिसत में मौत क्या है?

### परिचय:

- हरिसत में मृत्यु ऐसी मृत्यु को संदर्भित करती है, जो उस समय होती है जब कोई व्यक्ति विधि प्रवर्तन अधिकारियों की अभिरक्षा में होता है। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक बलप्रयोग, उपेक्षा या अधिकारियों द्वारा दुरव्यवहार।
- भारत के विधि आयोग के अनुसार, गरिफ्तार किये गए या हरिसत में रखे गए व्यक्तियों के वरिद्ध एक लोक सेवक द्वारा किये गया अपराध हरिसत में यातना के समान है।

### हरिसत में मौत के प्रकार:

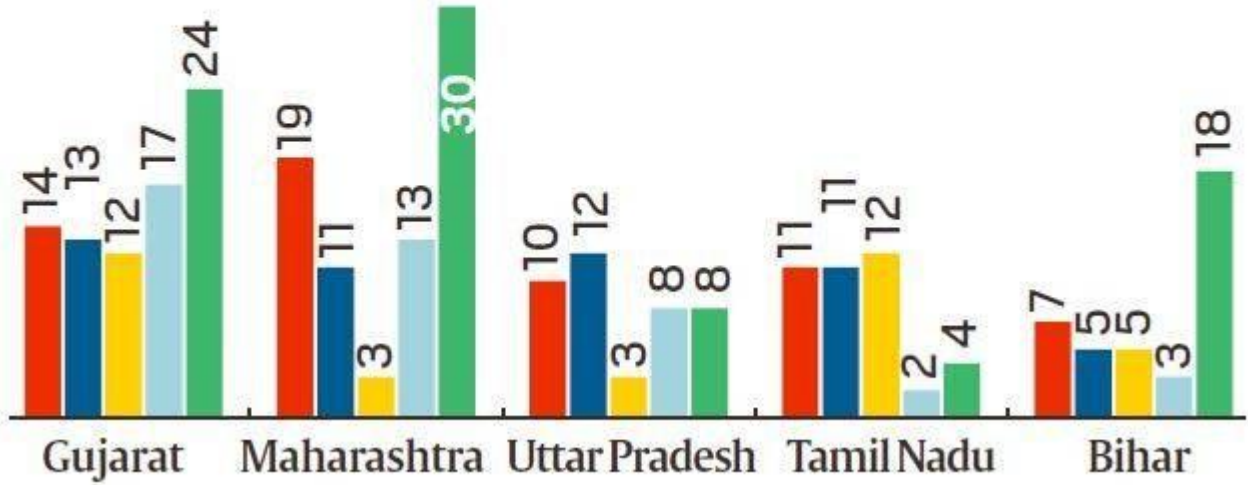
- पुलिस हरिसत में मृत्यु: पुलिस हरिसत में मृत्यु अत्यधिक बल, यातना, चकित्सा देखभाल से इनकार, या अन्य प्रकार के दुरव्यवहार या आकस्मिक कारण से हो सकती है।
- न्यायिक हरिसत में मृत्यु: न्यायिक हरिसत में मृत्यु भीड़भाड़, चकित्सा सुविधाओं की कमी, कैदी की हिसा या आत्महत्या के कारण हो सकती है।
- सेना या अर्द्धसैनिक बलों की हरिसत में मृत्यु: यह यातना या न्यायेत्तर हत्याओं के माध्यम से हो सकती है।

## पुलिस हरिसत और न्यायिक हरिसत:

पहलू	पुलिस हरिसत	न्यायिक हरिसत
हरिसत का स्थान	किसी पुलिस स्टेशन के हवालात या किसी जाँच एजेंसी के पास	मजिस्ट्रेट की हरिसत में जेल
न्यायालय के समक्ष उपस्थिति	24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष	जब तक न्यायालय से ज़मानत का आदेश नहीं आ जाता
प्रारंभ	शकियत मलिन या FIR दर्ज करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गरिफ्तारी के समय	सरकारी वकील द्वारा न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद जाँच के लिये आरोपी की हरिसत आवश्यक है।
अधिकतम अवधि	24 घंटे (उपयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)	आजीवन कारावास, मृत्यु या कम से कम दस वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिये 90 दिनि; अन्य अपराधों के लिये 60 दिनि

# STATES WITH HIGHEST CUSTODIAL DEATHS

■ 2017-18 ■ 2018-19 ■ 2019-20 ■ 2020-21 ■ 2021-22



//

## हरिसत में होने वाली मौतों पर रोक लगाना क्यों आवश्यक है?

- यह वधिद्वारा उचित व्यवहार किये जाने के व्यक्तियों के मूल अधिकार के वरिद्ध है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अर्गेंसट टॉरचर (UNCAT) का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो न्यायिक और पुलिस हरिसत में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार पर नयितरण लगाता है।
- हरिसत में यातना को रोकने के लिये सख्त नयिमों के अभाव में, भारत को वजिय माल्या जैसे लंबित न्यायिक कार्यवाही से बचने हेतु दूसरे देशों में शरण लेने वाले व्यक्तियों के प्रत्यर्पण में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है।
  - आर्थिक अपराधी प्रायः अपने प्रत्यर्पण मामलों में भारत में हरिसत में यातना पर नयिमों में लचीलेपन का हवाला देते हैं।
- हरिसत में यातना, हरिसत में लिये गए व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकती है क्योंकि पुलिस उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें क्रूर व्यवहार, यौन शोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है साथ ही समाज उनसे घृणा करने लगता है। उदाहरण: वर्ष 1972 में मथुरा में हरिसत में बलात्कार का मामला।

## हरिसत में मौत से संबंधित संवैधानिक और वधिकि ढाँचा क्या है?

- संवैधानिक प्रावधान:
  - भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्वगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिसमें यातना व अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सज़ा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
  - अनुच्छेद 20 किसी आरोपी व्यक्तियों को मनमानी और अत्यधिक सज़ा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या वदेशी या कंपनी या नगम के समान वधिकि इकाई हो। इसके अंतर्गत तीन प्रावधान शामिल हैं:
    - जनिमें अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण:- (अनुच्छेद 20(1)), दोहरे दंड से सुरक्षा:- अनुच्छेद 20(2) और आत्म-अपराध के वरिद्ध सुरक्षा:- अनुच्छेद 20(3) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
    - इसके अतिरिक्त, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में न्यायालय ने कहा कि राज्य किसी भी व्यक्तियों की सहमति के बिना उसका नारको-वशिलेषण, पॉलीग्राफ और बरेन-मैपिंग परीक्षण नहीं कर सकता है।
- वधिकि सुरक्षा:
  - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 में यह प्रावधान है, कि जाँच एजेंसियों की धमकी के आगे झुककर आरोपी द्वारा की गई सभी स्वीकारोक्तियाँ न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होंगी।
    - यह धारा मुख्य रूप से आरोपी को उसकी इच्छा के वरिद्ध बल प्रयोग के कारण बयान देने से रोकने का कार्य करती है।
  - भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 330 और 331, किसी भी व्यक्तियों से अपराध स्वीकारोक्तियाँ सूचना प्राप्त करने के लिये स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुँचाना अपराध मानती है।
  - सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिये वर्ष 2009 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 में संशोधन किया गया था, जिसमें:
    - पूछताछ के लिये गरिफ्तारियों और हरिसत में लेने के लिये उचित आधार एवं दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं को नरिधारित किया गया।
    - गरिफ्तारियों को परिवार, दोस्तों और जनता के लिये पारदर्शी बनाया जाता है तथा वधिकि प्रतनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

## हरिसत में यातना के वरिद्ध अंतरराष्ट्रीय अभसिमय क्या हैं?

- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वधि, 1948:
  - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वधि में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना और अन्य बलपूर्वक कार्यवाहियों से संरक्षित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945:
  - यह कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैदी होने के बावजूद, उनकी मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध में निर्धारित हैं।
  - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वधि में एक प्रावधान है, जो लोगों को यातना और अन्य बलपूर्वक कार्यवाहियों से संरक्षित करता है।
- नेल्सन मंडेला नयिम, 2015:
  - नेल्सन मंडेला नयिमों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में कैदियों के साथ अंतरनिति गरमा के साथ व्यवहार करने एवं यातना तथा अन्य दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिये अपनाया गया था।
- यातना के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभसिमय (UNCAT):
  - यह संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसका उद्देश्य विश्वभर में यातना और क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक कृत्य या सज़ा के अन्य कृत्यों को रोकना है।

## हरिसत में यातना से नपिटने के लयि उपाय:

- कानूनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:
  - सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सहि मामला, 2006 के आदेशों के समान व्यापक कानून स्थापित करना, जो विशेष रूप से हरिसत में यातना को अवैध बनाता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस व्यवस्था में बेहतर सुधार हेतु जाँच और कानून व्यवस्था के कार्यों को पृथक करने, राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसमें सविलि सीसाइटी के सदस्य होंगे तथा एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
  - हरिसत में यातना के आरोपों की त्वरति और नषिपक्ष जाँच सुनिश्चित करना।
  - नषिपक्ष और शीघ्र सुनवाई के माध्यम से अपराधियों को जवाबदेह बनाना।
- पुलिस सुधार और संवेदनशीलता:
  - मानवाधिकारों और गरमा के सम्मान पर ज़ोर देने हेतु पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर जवाबदेही, व्यावसायिकता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - हरिसत में यातना के मामलों की प्रभावी ढंग से नगिरानी और समाधान करने के लिये नरीक्षण व्यवस्था (oversight mechanism) की स्थापना करना।
- नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों को सशक्त बनाना:
  - हरिसत में यातना के पीड़ितों की सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिये नागरिक समाज संगठनों को प्रोत्साहित करना।
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के बाद भी किसी मामले की जाँच करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
    - सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उचित उपायों के साथ इसके अधिकार क्षेत्र का वसितार किया जाना चाहिये।
  - पीड़ितों व उनके परिवारों को सहायता और कानूनी सहायता प्रदान करना।
  - नविरण और न्याय पाने हेतु अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नकियों एवं संगठनों के साथ सहयोग करना।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न.1 मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? वशिलेखण कीजयि। (2014)

प्रश्न.2 भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को

सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनज़िम) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टपिपणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजयि। (2014)

